

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 29 नवम्बर, 2014

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0:- 22/2012 में जनपद हरिद्वार में पुराना नहर पुल से मछली बाजार होते हुए एन0एच0-73 तक क्षतिग्रस्त सड़क का बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण एवं नाले व 15 मी0 स्पान की पुलिया के निर्माण की पुनरीक्षित स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0:- 22/2012 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में पुराना नहर पुल से मछली बाजार होते हुए एन0एच0-73 तक क्षतिग्रस्त सड़क का बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण एवं नाले व 15 मी0 स्पान की पुलिया के निर्माण की स्वीकृति शासनादेश सं0:- 1273/111(2)/13-50(प्रा0आ0)/2012 दिनांक:- 20-02-2013 के द्वारा लम्बाई 1.28 किमी0 + 15 मी0 स्पान पुलिया तथा ₹ 229.28 लाख की प्रदान की गई है।

उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 20-02-2013 द्वारा स्वीकृत लागत ₹ 229.28 लाख में कार्य पूर्ण न हो पाने के फलस्वरूप क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 देहरादून द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित विस्तृत आगणन, जिसकी सम्पूर्ण लागत ₹ 355.37 लाख (₹ 229.28 लाख पूर्व स्वीकृत लागत + ₹ 126.09 लाख पुनरीक्षित लागत) है, के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई धनराशि ₹ 348.01 लाख (₹ 229.28 लाख पूर्व स्वीकृत लागत + ₹ 118.73 लाख पुनरीक्षित लागत) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय किये जाने की, महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश सं0:- 1273/111(2)/13-50(प्रा0आ0)/2013 दिनांक:- 20-02-2013 द्वारा स्वीकृत लागत ₹ 229.28 लाख को प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई सम्पूर्ण लागत ₹ 348.01 लाख से घटाते हुए, पुनरीक्षित लागत ₹ 118.73 लाख (₹ एक करोड़ अठ्ठारह लाख तिहत्तर हजार मात्र) में अवशेष कार्यों को पूर्ण करा लिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि, आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई हो अथवा अवशेष हो तो उस धनराशि को स्वीकृत लागत से समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यों पर अवमुक्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी। यह शासनादेश केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

3- उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण लागत ₹ 348.01 लाख के सापेक्ष ₹ 0.60 लाख की लागत के कार्यों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

5- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

6- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

- 8- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
- 9- स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।
- 10- पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- 11- उक्त योजना पर होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०:-22 लेखापीर्शक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-01 चालू निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य की मद से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से किया जायेगा।
- 12- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा विभिन्न पत्रावलियों में दिये गये परामर्शानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या:- 5984 (1)/111(2)/14-50(प्रा०आ०)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी हरिद्वार।
4. मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., देहरादून।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ललित मोहन आर्य)
संयुक्त सचिव